

अर्थव्यवस्था · Economy

आरबीआई एमपीसी मिनट्स जारी, 2.70 लाख निकायों में राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान

आरबीआई ने एमपीसी बैठक के मिनट्स जारी कर मुद्रास्फीति पर सतर्क रुख स्पष्ट किया, वहीं वित्त मंत्रालय ने ग्राम व शहरी निकायों में व्यापक वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया।

अर्थव्यवस्था · Economy

1. आरबीआई एमपीसी मिनट्स 2026

- रेपो दर 5.50% और एसडीएफ दर 5.25% पर निर्धारित
- गवर्नर ने दिए संकेत: भावी दर चक्र आंकड़ों व मुद्रास्फीति फैलाव पर निर्भर
- FY27 में जीडीपी वृद्धि 7.1% और खुदरा महंगाई 5.2% रहने का अनुमान

अर्थव्यवस्था · Economy

2. राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान

- 2.70 लाख ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों में अभियान शुरू
- 31 दिसंबर तक PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना की संतृप्ति
- रबी सीजन से पहले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरण पर विशेष जोर

अर्थव्यवस्था · Economy

3. बैंकिंग साइबर सुरक्षा और निगरानी

- बैंकों में डेटा सुरक्षा व अनुपालन पर नियामकीय चौकसी तेज
- CERT-In को 6 घंटे के भीतर साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य
- DPDP अधिनियम 2023 के तहत बैंकों की डेटा सुरक्षा जिम्मेदारी सुदृढ़

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

नीतिगत रेपो दर (वर्तमान)	5.50 प्रतिशत
-----------------------------	--------------

स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर	5.25 प्रतिशत
-------------------------------	--------------

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर	5.75 प्रतिशत
----------------------------------	--------------

वित्त वर्ष 2026-27 अनुमानित जीडीपी वृद्धि	7.1 प्रतिशत
--	-------------

अभियान में शामिल कुल निकाय/पंचायतें	2.70 लाख
--	----------

आरबीआई एमपीसी गठन की धारा	धारा 45ZB, आरबीआई अधिनियम 1934
------------------------------	-----------------------------------

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की किस धारा के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक समाप्त होने के 14वें दिन बैठक के मिनट्स प्रकाशित करना अनिवार्य है?

A धारा 45ZB

B धारा 45ZL

C धारा 42(1)

D धारा 45ZA

उत्तर / Answer: B — आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZL के तहत एमपीसी की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के मिनट्स 14वें दिन सार्वजनिक किए जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान के तहत कवर किए जाने वाले ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की कुल संख्या कितनी है?

A 1.50 लाख

B 2.10 लाख

C 2.70 लाख

D 3.50 लाख

उत्तर / Answer: C — वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 31 दिसंबर तक चलने वाला यह अभियान देशभर की 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किया जा रहा है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends